



11 June, 2024

प्रधानमंत्री आवास योजना

संदर्भ: हालिया कैबिनेट बैठक में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 30 मिलियन ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

योजना का समापन

- चूंकि वर्तमान केंद्र सरकार लगातार अपने दो कार्यकाल पूरे कर रही है, इसलिए इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक, 2022 तक सभी के लिए आवास (HfA) की योजना 2015 में PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजना के तहत बनाई गई थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लक्षित किया गया था।
- PMAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का वित्तीय योगदान है।
- मूल 2022 की समय सीमा के बावजूद, HfA एक दूर की वास्तविकता बनी हुई है।
- वर्ष 2022 में, सरकार ने PMAY-शहरी (PMAY-U) की अवधि को 31 दिसंबर, 2024 तक विस्तारित कर दिया था।

उद्देश्य:

- निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ झुग्गीवासियों का पुनर्वास करना।
- क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजनाओं (CLSS) के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी में किफायती आवास को शामिल करना।
- लाभार्थी-नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी) के लिए सब्सिडी उपलब्ध करना।

झुग्गी पुनर्विकास:

- यह योजना सामाजिक आवास में सार्वजनिक निवेश में अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% (विश्व बैंक: 49%) शहरी निवासी निर्दिष्ट और अनौपचारिक झुग्गियों में रहते हैं।
- पीएमएवाई की सफलता झुग्गियों में आवास संबंधी मुद्दों को संबोधित करने पर काफी हद तक निर्भर करती है।

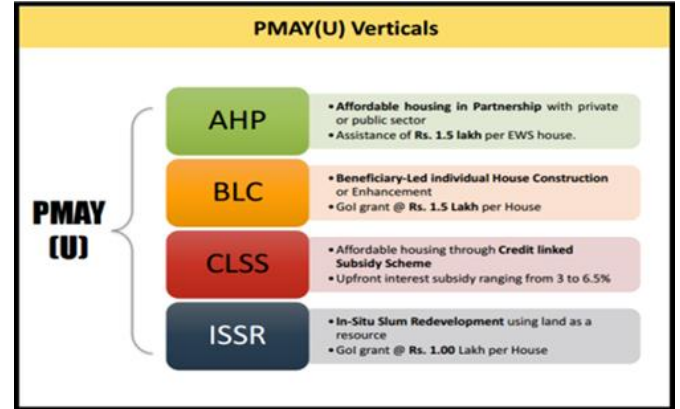
झुग्गी पुनर्विकास में मुद्दे:

- निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अक्सर ऊर्ध्वाधर विकास होता है, जिससे निवासियों के लिए अतिरिक्त समस्याएँ पैदा होती हैं।
- बहुमंजिला इमारतों में उपयोगिताओं के लिए उच्च आवृत्ति लागत लगती है, जो अक्सर निवासियों के लिए वहनीय नहीं होती।
- सीमित स्थान वाली निम्न डिजाइन वाली इमारतें अधिभोग को रोकती हैं।
- हवाई अड्डों, रेलवे और वनों के तहत पंजीकृत भूमि इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के लिए अनुपयुक्त है।
- आईएसएसआर योजनाएँ अक्सर समुदाय के इनपुट के बिना सलाहकारों द्वारा बनाई जाती हैं।
- शहर के मास्टर प्लान और पीएमएवाई-यू के बीच एक विसंगति मौजूद है, जिसमें सलाहकार सामाजिक आवास की तुलना में पूंजी-गहन समाधानों का पक्ष लेते हैं।

योगदान

- केंद्र कुल निवेश का लगभग 25% या ₹2.03 लाख करोड़ का योगदान देता है।
- राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकाय ₹1.33 लाख करोड़ का योगदान देते हैं।
- PMAY संरचना भूमिहीनों और गरीबों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती है।

- स्वीकृत किए गए लगभग 62% घर BLC के तहत हैं, जहाँ सरकार केवल लाभार्थियों के साथ लागत साझा करती है।
- कुल लाभार्थियों में से केवल 21% को सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है और लाभार्थी भूमि के मालिक होते हैं।
- कुल लाभार्थियों में से केवल 2.5% ISSR के तहत पुनर्वासित झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार हैं।



वनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

संदर्भ: रिपोर्ट, "महत्वाकांक्षा बढ़ाना, कार्रवाई में तेजी लाना: वनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने की दिशा में," ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के भीतर वन संरक्षण, प्रबंधन और बहाली में प्रमुख अंतरालों को उजागर किया।

वनों की कटाई से उत्सर्जन

- 2021 में ग्लासगो लीडर्स के वन और भूमि उपयोग पर घोषणा के बाद से वनों की कटाई से उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देते हुए 2030 तक वनों की हानि और भूमि क्षरण को रोकना है।
- वैश्विक वनों की कटाई के उत्सर्जन में वृद्धि मुख्य रूप से 2019 और 2022 के बीच लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए जिम्मेदार थी, अपवाद के रूप में ब्राजील, वनों की कटाई में 22% वार्षिक गिरावट दिखा रहा है।

एनडीसी प्रतिज्ञाएँ:

- 2017 और 2023 के बीच किए गए एनडीसी प्रतिज्ञाएँ 2030 तक वनों की कटाई को आधा करने और उलटने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाईं।
- सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 देशों में से केवल आठ ने अपने एनडीसी में वृक्ष आवरण के नुकसान को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- मेक्सिको ने 2030 तक शुद्ध शून्य वनों की कटाई को प्राप्त करने के लिए एक अनुकूलन लक्ष्य शामिल किया, जिसका लक्ष्य वनों की कटाई वाले क्षेत्र से मेल खाने या उससे अधिक क्षेत्र में वनों की कटाई करना है।
- बोलीविया ने 2030 तक वनों की कटाई को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से आधे से अधिक कमी अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर सशर्त है।
- कोटे डी आइवर ने 2030 तक 2015 के स्तर से 70% तक वनों की कटाई को कम करने का बिना शर्त लक्ष्य रखा है।
- कोलंबिया का लक्ष्य 2030 तक वनों की कटाई को 50,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष तक कम करना है और शुद्ध शून्य वनों की कटाई को प्राप्त करने के लिए 2015 पेरिस समझौते के तहत सहकारी दृष्टिकोण का उपयोग करना है।

Face to Face Centres





11 June, 2024

➤ प्रतिज्ञाओं में स्पष्टता का अभाव:

- रिपोर्ट में प्रतिज्ञाओं में स्पष्टता का अभाव पाया गया, जिसमें विभिन्न देश अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि क्षेत्र-आधारित लक्ष्य (हेक्टेयर), उत्सर्जन-आधारित लक्ष्य (CO₂ समतुल्य टन), या दोनों।
- कुछ देशों ने विस्तृत कार्य योजनाएँ प्रदान कीं, जैसे कि वन लक्ष्यों के लिए लाइबेरिया के '14 शमन क्रियाएँ और नीति उपाय', जबकि अन्य, जैसे कि मेक्सिको ने आगे कोई विवरण नहीं दिया।
- ब्राजील के अद्यतन NDC में वन-संबंधी लक्ष्यों का अभाव है, लेकिन इसमें 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए एक बहु-एजेंसी कार्य योजना शामिल है।
- इंडोनेशिया के NDC में विशिष्ट वन प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, लेकिन इसका लक्ष्य अपने FOLU नेट सिंक 2030 परिचालन योजना के माध्यम से 2030 तक वन और भूमि उपयोग क्षेत्रों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।

➤ शीर्ष 20 देशों से उत्सर्जन:

- वृक्ष आवरण हानि से सबसे अधिक उत्सर्जन वाले 20 देशों से NDC के भीतर प्रतिबद्धताएँ लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- 2019 और 2023 के बीच शीर्ष बीस देशों में उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से प्रति वर्ष औसतन 5.6 बिलियन टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जित हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन और शिपिंग से होने वाले सामूहिक उत्सर्जन से साढ़े चार गुना अधिक है।

➤ मुख्य सिफारिशें

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, कार्बन सिंक और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वन आवश्यक हैं।
- वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में पाम ऑयल, सोयाबीन और बीफ़ जैसी वस्तुओं की मांग से प्रेरित कृषि शामिल है।
- NDC और राष्ट्रीय नीतियों में वन-आधारित उपायों को मजबूत करना, बढ़ाना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- विकसित और वन देशों को अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
- रिपोर्ट में कार्बन बाजार में CO₂ उत्सर्जन के प्रति टन वन कार्बन की कीमतों में \$30-50 की वृद्धि करने की सिफारिश की गई है।
- स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की भागीदारी और उनके वन भूमि और कार्बन अधिकारों की मान्यता, प्रभावी वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अवैध गतिविधियों पर तीव्र कार्रवाई के माध्यम से मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन ने 2023 में ब्राजील के अमेज़न में वनों की कटाई में कमी लाने में योगदान दिया है।

➤ COP30 और भविष्य की प्रतिबद्धताएँ:

- अगले साल ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए पार्टियों का 30वाँ सम्मेलन (COP30) वन संरक्षण महत्वाकांक्षा के लिए एक मील का पत्थर है।
- जैसे-जैसे देश COP30 के लिए NDC सबमिशन के अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्ट में उनसे 2035 तक विस्तारित अपने संशोधित NDC में वनों पर टोस, मापने योग्य लक्ष्य शामिल करने का आग्रह किया गया है।

आदित्य-एल1

संदर्भ: इसरो ने सोमवार को घोषणा की कि उसके आदित्य-एल 1 अंतरिक्ष यान के दो ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग उपकरणों ने हाल ही में हुई सौर गतिविधि को कैचर किया है।

- सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) ने मई 2024 में गतिशील सौर गतिविधियों को कैचर किया।

- कई एक्स-क्लास और एम-क्लास फ्लेयर्स के साथ-साथ कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) दर्ज किए गए, जिससे महत्वपूर्ण भू-चुंबकीय तूफान आए।
- सक्रिय क्षेत्र AR13664 ने 8-15 मई के बीच कई एक्स-क्लास और एम-क्लास फ्लेयर्स का विस्फोट किया, जिसमें 8 और 9 मई को CME थे।
- 11 मई को एक बड़ा भू-चुंबकीय तूफान आया।

➤ आदित्य-एल1 मिशन

- यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित मिशन है।
- इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 2008 में संकल्पित किया गया।
- सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
- L1 स्थान सूर्य के निरंतर अवलोकन को बिना ग्रहण/अवसादन के अनुमति देता है।
- मिशन को L1 के चारों ओर हेलो कक्षा तक पहुँचने में लगभग 109 पृथ्वी दिन लगेंगे।
- विद्युत चुम्बकीय, कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए सात पेलोड ले जाते हैं।

➤ उपकरण और अवलोकन:

- उपकरणों को सौर वायुमंडल, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है।
- इन-सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे।
- चार पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे, और तीन L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन-सीटू अध्ययन करेंगे।

➤ पेलोड:

- विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ (VLEC):** कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए।
- सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT):** संकीर्ण और ब्रॉडबैंड में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग के लिए।
- सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS):** सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीट्री और सूर्य-ए-ए-स्टार अवलोकन के लिए।
- आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX):** प्रोटॉन और भारी आयनों सहित सौर वायु कणों का विश्लेषण करता है।
- हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS):** हाई एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीट्री और सूर्य-ए-ए-स्टार अवलोकन के लिए।
- आदित्य (PAPA) के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज:** इलेक्ट्रॉनों और भारी आयनों सहित सौर वायु कणों का विश्लेषण करता है।
- एडवांस्ड ट्राई-एक्सियल हाई-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर:** इन-सीटू चुंबकीय क्षेत्रों (Bx, By, Bz) को मापता है।

➤ वैज्ञानिक लक्ष्य:

- कोरोनल हीटिंग को समझना।
- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का अध्ययन करना।
- प्री-फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं की जाँच करना।
- अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता की जाँच करना।
- कण और क्षेत्र प्रसार का विश्लेषण करना।

➤ आदित्य-एल1 के उद्देश्य:

- सौर ऊपरी वायुमंडल (क्रोमोस्फीयर और कोरोना) की गतिशीलता का अध्ययन करना।

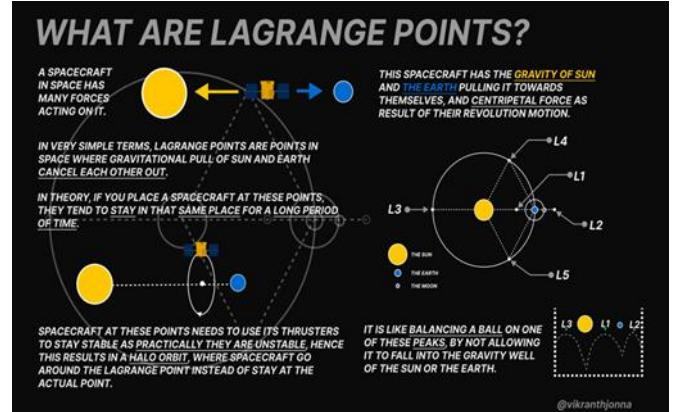
Face to Face Centres





11 June, 2024

- क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा भौतिकी और सीएमई और फ्लेयर्स की शुरुआत की जांच करना।
- सूर्य से कण गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इन-सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना।
- सौर कोरोना और इसके हीटिंग तंत्र के भौतिकी का विश्लेषण करना।
- कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना: तापमान, वेग और घनत्व।
- सीएमई के विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति की जांच करना।
- सौर विस्फोटक घटनाओं के लिए अग्रणी कई परतों (क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना) में प्रक्रियाओं की पहचान करना।
- सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्रों की माप करना।



NEWS IN BETWEEN THE LINES

नैनो-उर्वरक



हाल ही में, कृषि-समाधान प्रदाता कोरोमंडल इंटरनेशनल ने आंध्र प्रदेश में अपने काकीनाडा परिसर में ₹50 करोड़ की लागत से नैनो-उर्वरक संयंत्र स्थापित करके नई पीढ़ी के उर्वरकों के क्षेत्र में कदम रखा है।

नैनो-उर्वरकों के बारे में:

- नैनो-उर्वरक (NF) उर्वरकों के अत्यधिक कुशल प्रकार हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की वृद्धि में सुधार कर सकते हैं।
- ये नैनोकणों से बने होते हैं जिनमें नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K), आयरन (Fe) और मैंगनीज (Mn) जैसे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें नियंत्रित तरीके से पौधे तक पहुँचाया जाता है।
- इन उर्वरकों को पाउडर या तरल के रूप में मिट्टी या पौधों की पत्तियों पर लगाया जा सकता है।
- वे पोषक तत्वों की उपलब्धता को विनियमित करके, पोषण क्षमता को बढ़ाकर और पारंपरिक खनिज उर्वरकों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाकर पौधों की वृद्धि तथा फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं।
- उन्हें पारंपरिक उर्वरकों का एक आशाजनक विकल्प माना जाता है जो मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- ये पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले भी हैं एवं पर्यावरण को प्रदूषण तथा जल संदूषण से बचाने में मदद कर सकते हैं।
- भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने तरल नैनो-यूरिया का पेटेंट कराया है, जो दुनिया का पहला नैनो-उर्वरक है।

ब्रिक्स



हाल ही में, भारत ने रूस द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया का नए ब्रिक्स सदस्यों के रूप में स्वागत किया।

ब्रिक्स के बारे में:

- ब्रिक्स एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- 2006 में, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने "ब्रिक" समूह का गठन किया, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ, इस प्रकार इसका नाम बदलकर "ब्रिक्स" कर दिया गया।
- दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जहाँ नेता विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
- समूह को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- फोर्टलेजा (2014) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- एनडीबी 2016 में पूरी तरह से चालू हो गया और इसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया।

भारतीय गुणवत्ता परिषद ने हाल ही में भारत के 20 से अधिक शहरों में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया।

भारतीय गुणवत्ता परिषद



भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना की स्थापना और संचालन करना, राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान की निगरानी करना और उत्पादों, सेवाओं एवं प्रक्रियाओं के तीसरे पक्ष के आकलन के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- यह संगठन 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत था।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शासन, सामाजिक क्षेत्रों और बुनियादी ढाँचे सहित कई क्षेत्रों में काम करता है।
- इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष और 38 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो सरकार, उद्योग संघों, गुणवत्ता पेशेवर निकायों और उपभोक्ता संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Face to Face Centres





11 June, 2024

	इसने भारत के गुणवत्ता केंद्रों का जश्न मनाने, देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता: भारत का गुणवत्ता आंदोलन' अभियान शुरू किया है।
स्टिकी मुद्रास्फीति 	हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में स्टिकी मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं के कारण लगातार आठवीं बार रेपो दर को स्थिर रखा। स्टिकी मुद्रास्फीति के बारे में: - स्टिकी मुद्रास्फीति उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहाँ मुद्रास्फीति की दरें लंबे समय तक लगातार उच्च बनी रहती हैं। - यह मुद्रास्फीति मजदूरी-मूल्य सर्पिल, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं के बीच उच्च मुद्रास्फीति की लगातार अपेक्षाओं के कारण होती है। - यह क्रय शक्ति को कम करती है, व्यवसाय नियोजन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है और केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे उधार लेने की लागत के साथ आर्थिक विकास प्रभावित होता है। - केंद्रीय बैंकों को नीतिगत देरी के कारण ब्याज दर समायोजन के माध्यम से स्टिकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिससे मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति उपायों के प्रभावों को देखने में देरी होती है। - स्थिर मुद्रास्फीति के उदाहरणों में 1970 के दशक की मुद्रास्फीति शामिल है, जिसमें स्थिर आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति की विशेषता थी, और हाल के रुझान जहाँ विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और बढ़ी हुई मांग के कारण महामारी के बाद लंबे समय तक मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही हैं।
सुर्खियों में स्थल मॉरीशस	हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दिल्ली में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात की। मॉरीशस (राजधानी: पोर्ट लुइस) अवस्थिति: मॉरीशस अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जो मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। महत्व: - इसे लगातार सबसे शांतिपूर्ण अफ्रीकी देश का दर्जा दिया जाता है। - मॉरीशस के दक्षिण-पश्चिम में 556 मीटर ऊंचा पर्वत ले मोर्ने ब्रेबेट, गुलामी प्रतिरोध का प्रतीक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 975 में अरबों द्वारा खोजे गए, मॉरीशस ने बाद में पुर्तगाली और डच नाविकों की यात्राओं का स्वागत किया, जिसने इसके ऐतिहासिक महत्व में योगदान दिया। - मॉरीशस एक वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जो इसके शासन मॉडल को दर्शाता है। - मॉरीशस और भारत ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, इससे पहले कि मॉरीशस 1968 में स्वतंत्र हो गया। 

POINTS TO PONDER

- किस मंत्रालय ने हाल ही में 10,000 एफपीओ को सीएससी में बदलने के लिए सीएससी एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? – **कृषि मंत्रालय**
- 'विश्व महासागर दिवस 2024' का विषय क्या है? – **अवेकन न्यू डेप्थ**
- ए जे टी जॉनसिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? – **वन्यजीव संरक्षणवादी**
- हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में 2024 आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? – **सरबजोत सिंह**
- हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? – **बांग्लादेश**

Face to Face Centres

